तथा मशीनरी की खराबी तथा कम उत्पादकता। उपलब्ध जानकारी के अनुसार सरकारी क्षेत्र के 19 उपक्रमों में वर्ष 1991–92 के दौरान केवल जिस वर्ष की नवीनतम जानकारी उपलब्ध है, बिजली की कमी के कारण उत्पादन बुरी तरह प्रभावित हुआ। इन उपक्रमों के नाम विवरण (नीचे देखिए) में दिये गये हैं। इस संबंध में किये गये उपचारी उपाय हैं–निजी विद्युत संयंत्रों की स्थापना करना, प्रौद्योगिकी का आधुनिकीकरण तथा उसे समुन्नत बनाना, ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा के वैकल्पिक साधनों का उपयोग करना आदि।

विवरण

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के नाम

1. भारतीय सीमेंट निगम लि0
2. कोल इंडिया लि0
3. दामोदर सीमेंट एण्ड स्लैग लि0
4. भारतीय उर्वरक निगम लि0
5. फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स (त्रावणकोर) लि०
6. भारी इंजीनियरी निगम लि0
7. हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपो0 लि0
8. हिन्दुस्तान इंसैक्टीसाइड्स लि0
9. हिन्दुस्तान पेपर कारपो0 लि0
10. हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपो0 लि0
11. हिन्दुस्तान जिंक लि0
12. कुद्रेमुख आयरन ओर कंपनी लि0
13. मद्रास फर्टिलाइजर्स लि0
14. मिश्रधातु निगम लि0
15. नागालैण्ड पल्प एण्ड पेपर कंपनी लि0
16. तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग
17. राष्ट्रीय कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि0
18. टेनरी एण्ड फुटवियर कारपो0 आफ इंडिया लि0
19. विश्वेश्वरैया आयरन एण्ड स्टील लि0

Establishment of salt manufacturing units near Kandla

1966. SHRI MENTAY PADMANABHAM: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether the Salt Commission has submitted a report advocating objections to the establishment of a large salt manufacturing unit near Kandla by Messrs Cargill a US multi-national;

(b) what are the details of the objections raised by the Salt Commissioner to this proposal;

(c) what action has been taken in this regard;

(d) whether it is a fact that Ministry as soft-pedalled the report of the Salt Commissioner;

(e) if so, the reasons therefor;

(f) whether the report has categorically stated that the surplus of salt already exceeds lakhs of tons per annum; and

(g) whether any proposal has been put to Cargill by Government to produce salt and then sell it, rather than clear the existing proposal?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT) WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (DEPARTMENT OF HEAVY INDUSTRY) (SMT. KRISHNA SAHI): (a) to (f) A letter of permission has been issued to M/s. Cargil South-East Asia Ltd. Singapore in August, 1992 to set up a 100 per cent EOU in Kutch Distt. of Gujarat for manufacture of 10 lakhs tonnes of solar salt per annum. The party had later on approached Kandla Port Trust for allotment of 15,000 acres of land, which was not approved by the Kandla Port Trust Board. The Government has not received any report whatsoever from the Salt Commissioner in this regard.

(g) No, Sir.